(ग) से (ङ) सरकार मूल्यों में घटबढ पर गहरी नजर रखती है और मूल्य वृद्धि को संतुलित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है। प्रशासित मदों के मूल्य समय-समय पर, चयनात्मक रूप से उर्ध्वगामी समायोजित किए जाते हैं। जो अपरिहार्य लागत वृद्धियों को दर्शाते हैं तथा यह ध्यान रखा जाता है कि उद्योग प्रचालनों में सुधरी हुई कुशलता के माध्यम से अनुत्पादक लागत संघटकों को समाहित कर सके।

Prosecution against M/s ITC Ltd., Calcutta

3677. SHRIMATI MIRA DAS:

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY:

SHRI SUBRAMANIAN SWAMY:

SHRI CHIMANBHAI MEHTA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to Unstarred Question 2840 given in the Rajya Sabha on the 4th August, 1992 and state;

(a) whether the prosecution against M/s. ITC Ltd., Calcutta has since been launched in the competent court in Calcutta and the concerned Collectors have been advised accordingly;

(b) if not, what are the reasons that prosecution has not been launched so far; and

(c) whether Government propose to deal with all the tax evaders in the same manner?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Prosecution against M/s. ITC Ltd., Calcutta has not yet been launched in the competent court in Calcutta.

(b) Some complex issues are involved in the launching of prosecution against M/s. ITC, causing delay. One of the issues was whether prosecution is to be launched only against the Company or also against the officials of the Company. Another issue involved was the selection of the place from where prosecution was to be launched. Legal opinions were obtained initially from Special Public Prosecutors in different States and subsequently from Law Officers. The opinion received, inter alia, was prosecution can be launched against both the company, its Directors and Officers responsible for the commission of the offence. Further, it will be advisable to launch the prosecution at one place, namely, Calcutta. Advice was also received to the effect that it will not be possible to make one composite complaint for the entire period of 1-10-75 to 28-2-83; it has to be a yearwise break up of offences. Special Public Prosecutors were accordingly appointed to deal with the case including drafting of complaints. As the present addresses of the persons to be prosecuted have to be incorporated in the draft complaint, necessary verification had to be carried out with the help of field formations. Year-wise involvement of duty is being collected from the respective Collectorates of Central Excise with reference to voluminous records.

(c) The Government deals with all tax evaders with necessary firmness and severity.

लम्बित वित्तीय मामले

3678. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठ मलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में दिसम्बर, 1992 तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिकरणों में अनेकों वित्तीय विवाद निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इन मामलों में अदालतों और अधिकरणों द्वारा स्थगनादेश आरम्भिक अवस्था में दे दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप काफी मात्रा में धन-राशि रुकी पड़ी है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने मामले हैं और स्थगनादेश के कारण कुल कितनी धन-राशि रुकी पड़ी हुई है, और

(घ) सरकार द्वारा कितने मामलों में स्थगनादेश रद्द करने अथवा हटाने का प्रयास किया गया है और उसे कितने मामलों में सफलता मिली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधिकरणों में लम्बित पड़े वित्तीय विवाद सरकार द्वारा किए गए विभिन्न इकरारनामों, करारों आदि से सम्बन्धित होंगे। ऐसे मामलों के ब्यौरे केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते।

राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अदालत की स्थापना

3679. **श्री शारदा महन्ती :**
श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :
डा० बापू कालदाते :
श्री सोम पाल :

क्या **वित्त** मंत्री 9 मार्च, 1993 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 1664 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अदालत की स्थापना हेतु प्रस्तावित विधान को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और इस अदालत की स्थापना कब तक कर दी जाएगी;

(ख) इस समय आयकर के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें से एक लाख से अधिक की आयकर राशि अन्तर्ग्रस्त है और ये मामले कब से लम्बित हैं ; और

(ग) लम्बित मामलों को कब तक निपटा लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :) (क) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायाधिकरण को स्थापित किए जाने के निमित्त विधान को अपेक्षित अन्तर विभागीय परामर्शों को पूरा किए जाने के पश्चात् पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है।

(ख) और (ग) : दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार एक लाख रु० से अधिक की बकाया मांग वाले, 48,384 मामले विचाराधीन पड़े हुए थे। बकाया मांग वाले मामलों का परिसमापन निरन्तर चलने वाली एक प्रक्रिया है। चूंकि न्यायिक/अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया अपना पूरा समय लेती है, इसलिए इस प्रकार के मामलों को निपटाने में कितना समय लगेगा इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती।

Request for Exempting Fodder Additives from Central Excise

3680. SHRI MOHINDER SINGH LATHER: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the compound live stock feed manufacturing association, in a representation, have requested Government to exempt the fodder additives from the levy of Central Excise and States Sales Tax considering it as animal's feed:

(b) if so, whether Government propose to exempt the levy's on fodder additives: and

(c) if not, what are the reasons therefor stating its overall impact on the manufacturing units in the country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Representations from the Compound Livestock Feed Manufacturing